

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 44/22

GCMS NO 2022/78

नसरुद्दीन पुत्र हाजी तैयब गद्दी जाति मुसलमान गद्दी निवासी गौगोर तहसील व जिला सवाई
माधोपुर

अपीलांट

बनाम



- समिसू पुत्र छीतर
इस्लाम पुत्र छीतर
3. नफीस पुत्र कमरुद्दीन समस्त जातियान मुसलमान ग्राम गौगोर तहसील व जिला सवाई
माधोपुर
 4. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

रैस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 16/16 निर्णय दिनांक 18.5.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री इंसाफ अली

अभिभाषक रैस्पो0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

दिनांक 12.05.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.5.22 न्यायालय उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है।


अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 एक ही गांव के रहने वाले हैं। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 930 रकबा 0.19 है0 , ख0न0 931 रकबा 0.21 है0 , ख0न0 932 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम गौगोर मे मौजूद है। उक्त आराजी मे आने जाने का एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 933 रकबा 0.43 है0 की मेड से ग्राम मैनपुरा से धनोली जाने वाली नहर की पाल वाले आम रास्ते पर आते जाते हैं। प्रार्थी उक्त खेत ख0न0 932 से नहर की पाल वाले आम रास्ते की दूरी लगभग 150-200 फीट की है इसके अलावा प्रार्थी को उक्त आम रास्ते से अपने खेत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपने खेत खसरा न0 932 से पाल पर बने आम रास्ता पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 के उक्त खेत खसरा न0 933 से वर्षों से निकलता आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज नहीं है। दिनांक 20.10.16 को प्रातः 10 बजे करीब अप्रार्थीगण उक्त खेत खसरा न0 933 की तारबंदी कर रहे थे तब प्रार्थी ने कहा कि इस मेड पर तारबंदी क्यों कर रहे हो इस मेड के रास्ते से प्रार्थी वर्षों से अपने खेत खसरा न0 932 पर वर्षों से आता जाता रहा है। इस बात पर अप्रार्थीगण प्रार्थी से झगडा फिसाद करने लगे तथा मेड के रास्ते से आने जाने के लिए मना कर दिया। अतः प्रार्थी को अपने खेत खसरा न0 930,931 व 932 वाके ग्राम गौगोर तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर से ग्राम मैनपुरा से धनोली जाने वाली नहर की पाल पर बने आम रास्ते तक आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा न0 933 वाके ग्राम गौगोर की मेड पर होकर 10 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में तरमीम कराने के आदेश प्रदान किये जाने। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) खारिज किये जाने व्यथित होकर अपीलांट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।


अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक व दिनांक के कॉलम न0 5 में स्पष्ट अंकित है कि अपीलांट को रास्ते की सख्त आवश्यकता है। उसे अन्य कोई अल्टरनेट रास्ता मौजूद नहीं है। जिससे साफ जाहिर है कि अपीलांट वर्षों से इसी रास्ते से आवागमन करता है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलांट की ग्राम गौगोर में स्थित भूमि खसरा न0 930,931 व 932 में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए रास्ता सबसे निकटतम भूमि खसरा न0 933 रकबा 0.43 है0 की मेड से होकर उपलब्ध कराया जावे। इसी मेड पर नहर का धोरा (पानी की नाली) है। जिससे स्वयं व अन्य खातेदारों की 60 से अधिक भूमि की पीलाई की जाती है। धोरे का पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी जिक्र है। रेस्पो0 की आराजी ख0न0 933 व अपीलांट की स्वामित्व की आराजी ख0न0 930,931 व 932 मौके पर चरपेटवा है जिसमें होकर अपीलांट को रास्ता दिया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को अनदेख कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलांट वर्षों से अपनी आराजी में आवागमन इसी भूमि खसरा न0 933 की मेड पर स्थित धोरे से होकर आवागमन करता रहा है मौका रिपोर्ट भी स्पष्ट करती है कि अपीलांट को रास्ते की आवश्यकता है। और कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई दोनों रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र 251 ए खारिज कर अहम भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय को धारा 251 क की मंशा व प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर निर्णय पारित करना चाहिए था। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट के नाम दर्ज भूमि खसरा न0 963 रकबा 0.37 है0 ख0न0 964 रकबा 0.10 है0 रेस्पो0 के कब्जे की भूमि की सीध में होकर मानकर एवं नहर की पाल पर स्थित होना मानकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने में अहम भूल की है। अपीलांट अपनी आराजी पर वर्षों पूर्व से रेस्पो0 के कब्जे के खसरा न0 933 की मेड जो नहर की पाल से होकर मुख्य सड़क को मिलती है में से होकर अपीलांट आता जाता रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को गौर नहीं किया है कि


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नहर की पाल (धोरा) सिचाई विभाग (सार्वजनिक निर्माण विभाग) द्वारा 171 बीघा भूमि खातेदार से एक्वायर कर जिस पर उची उची पाल (धोरा) खातेदारी भूमि मे होकर निकाली है । मगर नक्शा शीट मे तरमीम व इन्द्राज नही होने से उक्त भूमि मात्र खातेदारी इन्द्राज है। मगर इसका उपयोग आवागमन व नहर का पानी देने से सार्वजनिक रूप से करते है। जिसे खातेदार बंद नही कर सकता। यदि उक्त धोरे को अवरुद्ध करने का अधिकार होता है तो पहले निकलने की कौशिल्य दिया एवं धोरे की भूमि खातेदार के लिए यूजलेस है। जिस पर कृषि नही होती जो पडत की तारीफ मे आती है जो रास्ता देने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्य दस्तावेजी का सही तरीके से अवलोकन नही कर मात्र सरसरी तौर पर अपने निर्णय मे यह फाईडिंग देते हुए कि अपीलान्ट की आराजी ख0न0 961,962,963 मे होकर रास्ता सुविधाजनक रहेगा कहकर इल्लीगल इम्प्रोजर व इन करेक्ट निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है क्योकि खसरा न0 961,962 व 963 मे अपीलान्ट के हिस्से की और बोर लगा हुआ है डिप सिस्टम मे डिप लगी है तथा 15 वर्ष पुराना अमरुदो का बगीचा लगा है। जिसमे से रास्ता लेना संभव नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट की अनदेखी की है जबकि प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित चाहे गये रास्ते की लम्बाई व चौडाई की डी एल सी दर से दो गुना राशि अपीलान्ट जमा करवाने को तैयार होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट /प्रार्थी द्वारा चाही गई रिलीफ पर गौर नही कर अहम कानूनी भूल की है। इसलिये निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 251 क प्रस्तुत करते ही रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने विवादित आराजी का बेचान कर दिया गया। जिसे भी रेस्पो0 संख्या 3 बनाया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपीलान्ट/प्रार्थी की ग्राम गौगोर मे स्थित भूमि हाल खसरा न0 930,931 व 932 मे कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु रेस्पो0 संख्या 3 के नाम दर्ज भूमि खसरा न0 933 की मेड पर होकर रास्ता उपलब्ध कराया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथो से पेश नही किया है क्योकि हाल ट्रेसशीट के अनुसार खसरा न0 963 रकबा 0.37 है0, 964 रकबा 0.10 है0 प्रार्थी/अपीलान्ट के नाम खातेदारी मे दर्ज है एवं मौके पर नहर के उपर स्थित है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी/अपीलान्ट को रेस्पो0 द्वारा खरीद की गई भूमि खसरा न0 933 व 934 की नहर के उपर स्थित होने से प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से खारिज किया गया है। अपीलान्ट एवं रेस्पो0 के नाम दर्ज भूमियां एक ही सीध मे एवं नहर के उपर स्थित है। अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे इस तथ्य को छिपाया है कि खाता संख्या 135 मे अंकित खसरा न0 963 ,964 नहर की पाल पर रेस्पो0 की भूमि की सीध मे मौजूद है जिसके बाबत प्रार्थना पत्र मे इन खसरा न0 का इन्द्राज नही किया है। जबकि प्रार्थी/अपीलाट के ख0न0 963 व 964 नहर की पाल मे रेस्पो0 की सीध मे स्थित है तो उसको रास्ते की कहां आवश्यकता है वह अपनी आराजीयात ख0न0 930,931 व 932 आवागमन कर सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी कारण प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट मे भी


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थी/अपीलांत द्वारा तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है साथ ही सिचाई विभाग आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसको प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक निर्णय है। अतःअपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांत/प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी खसरा न0 930,931 व 932 पर आने जाने हेतु रेस्प0 की आराजी खसरा न0 933 में से रास्ता चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिसमें तहसीलदार द्वारा स्पष्ट अंकन किया है कि प्रार्थी/अपीलांत की खातेदारी की भूमि खसरा न0 930,931 व 932 पर आवागमन हेतु खसरा न0 933 के अलावा खसरा न0 939,940,840,845,935 व 934 में होकर आवागमन सुविधाजनक है। परन्तु अपीलांत द्वारा केवल मात्र खसरा न0 933 में से ही रास्ता चाहा गया है। इसी कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांत का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। रास्ता एक अत्यधिक आवश्यकता है जो किसी खातेदार आसामी की जोत पर पहुँच के लिए आवश्यक है। रास्ते के अभाव में खातेदार को उस भूमि की फसल काश्त से बंचित होता है। इस प्रकार अपीलांत/प्रार्थी को रास्ता प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त विवेचन से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थी/अपीलांत की खातेदारी की भूमि ख0न0 930,931 व 932 पर पहुँच हेतु सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ते हेतु तहसीलदार से पुनःतथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जाकर एवं जिस खातेदार की भूमि में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हो उसके खातेदार को तलब किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांत रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मुकदमा न0 16/16 में पारित निर्णय दिनांक 18.5.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में ख0न0 930,931 व 932 पर पहुँच हेतु सबसे निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ते हेतु तहसीलदार से पुनःतथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की जाकर एवं जिस खातेदार की भूमि में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हो उसके खातेदार को तलब किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ दिनांक 9.6.2025 को उपस्थित होंगे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
राजस्थान अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर